

13.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

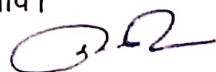
प्रार्थी अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उनय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि मौजा-बालेबा, तह0 गडरारोड के खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 104 बीघा, खसरा नम्बर 188 रकबा 77.03 बीघा अर्थात् 124345 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 78.15 बीघा अर्थात् 127476 हैक्टैयर किस्म बा.दो. व खसरा नम्बर 861/555 रकबा 1.08 बीघा अर्थात् 02266 हैक्टैयर सहित मौजा-चारगों की ढागी, पटवार नग्डल-बालेबा तह0 गडरारोड जिला बाडनेर में खेत खसरा नम्बर 370 रकबा 1.05 बीघा किस्म गै.मु. ढागी व खसरा नम्बर 512 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 808/512 रकबा 2.19 बीघा किस्म बा.सो. खसरा नम्बर 809/512 रकबा 13.10 बीघा किस्म बा.सो. खसरा नम्बर 810/512 रकबा 0.09 बीघा किस्म बा.सो. की के आये हुए हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी जो वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीनी के दादी सतुर तगाराम पुत्र सोनाजी नाई के नाम खातेदारों ने दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 808/512, 809/512 व 810/512 में प्रार्थीनी चिनुदेवी पत्नी अर्जुनराम का 1/9 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 611 व 188 में प्रार्थीनी का 1/18 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 555 व 861/555 में प्रार्थीनी की दादी सास वरजू देवी का देहान्त हो जाने से उक्त खसरा नम्बर 555 रकबा 127476 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 861/555 रकबा 0.2266 में प्रार्थीनी का 1/12 हिस्सा है इसलिये प्रार्थीनी अपने भविष्य के जीवन हेतु वादग्रस्त आराजी ने अपना उपर वर्णित हिस्सा घोषित करवा कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने की अधिकारी है साथ ही प्रार्थीनी के उक्त हिस्से पूर्व में विप्रार्थी नखतारु द्वारा किये गये बेचान व उस पर भरे गये नानान्तकरण को निरस्त करवाने की अधिकारी है विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित नही करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह भाटी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी स्व. तगाराम की वक्त सेटलमेन्ट की आवगी भूमि थी। तगाराम के देहान्त उपरान्त उनके पुत्रों के नाम अवश्य दर्ज हुई। प्रार्थीना ने अपने



22

आवेदन पत्र मे स्वीकार किया है कि उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। इसके जवाब मे निवेदन है कि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है। जो चार पीढी पुरानी हो और पिछली तीन पीढियों द्वारा उस सम्पत्ति मे बंटवाडा विभाजन नहीं होना आवश्यक है। अगर पैतृक संपत्ति में बंटवाडा हो जाता है तो वह संपत्ति पैतृक नहीं होकर स्व. अर्जित संपत्ति कहलाती है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी संपत्ति का विभाजन उपरान्त बेचान किया गया है। जो कि विप्रार्थी संख्या 1 की स्व. अर्जित संपत्ति होने प्रार्थीया का पैतृक संपत्ति को आधार पर कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान होने की हैसियत से अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं एवं परिवार के लालन पालन व अप्रार्थी संख्या 1 नखता राम के पुत्र अर्जुनराम के लाइलाज बिमारी से लगातार 10 वर्षों से ग्रसित होने के कारण इलाज हेतु अस्पताल खर्चो हेतु पैसो की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी स्व अर्जित भूमि का अलग-अलग क़ेताओं को बेचान किया गया अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा खसरा नम्बर 555 व 188 भूमि का जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज क़य किया। दस्तावेज पंजीयन उपरान्त ही मुझ विप्रार्थी संख्या 5 को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जो कि विधिवत बेचान होने की पुष्टि विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तो से होती है। इस कारण किसी भी बेचान दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से यह राजस्व आवेदन क्षेत्राधिकार विहिन होने से चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थी संख्या 5 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने एवं मौके पर वक्त क़य से आज दिन तक निरन्तर कब्जा काशत होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीया का कोई राजस्व रेकर्ड नहीं होने एवं मौके पर कब्जा काशत नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीनी की बजाय अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष मे प्रमाणित होता है। माननीय उच्च न्यायालयो के न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार रेकर्ड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी क बजाय अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में प्रमाणित होने से आवेदन खारिज योग्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण के पक्ष मे होने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

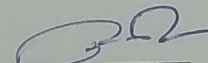


1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थनी विवादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से ही रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।
2. सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान करने से आज दिनांक तक केवल विप्रार्थीगण का ही मौके पर कब्जा काशत होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थनी के पक्ष में सिद्ध नहीं होना पाया जाता है।
3. अपूर्णाय क्षति :- कि प्रार्थनी वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार नहीं होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काशत प्रार्थनी का नहीं होने से अपूर्णाय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थनी के पक्ष में सिद्ध नहीं होना पाया जाता है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थनी के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी दि. 16.04.2024 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसे आगे बढ़ाया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थनी के पक्ष में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.04.2024 को निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
गडरारोड़